भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.55

उत्तर देने की तारीख 02 फरवरी, 2024

उच्च गुणवत्ता वाले इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी की उपलब्धता

55. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार राज्य के वन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता और हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उत्तर पूर्वी राज्यों, देश के द्वीपों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सशस्त्र बलों के कर्मियों और स्थानीय लोगों के लिए कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए चुनौतीपूर्ण और दूरदराज के इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ग) पिछले लगभग 10 वर्षों में बिहार में दूरसंचार कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है:

- बिहार लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की कुल संख्या मार्च 2014 में 34,176 थी जो बढ़कर दिसंबर 2023 में 1,99,887 हो गई है।
- मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या मार्च 2014 में 6.15 करोड़ थी जो बढ़कर नवंबर 2023 में 9.35 करोड़ हो गई है।
- इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सितंबर 2014 में 1.29 करोड़ थी जो बढ़कर जून 2023 में 6.76 करोड़ हो गई है।

पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में दूरसंचार कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेस ट्रांस-रिसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या मार्च 2014 में 20,106 थी जो बढ़कर दिसंबर 2023 में 1,09,128 हो गई है।
- तदनुसार मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या मार्च 2014 में 2.47 करोड़ थी जो बढ़कर नवंबर 2023 में 3.8 करोड़ हो गई है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) मार्च 2014 में 35,315 किलोमीटर थी जो बढ़कर सितंबर 2023 में 1,35,306 किलोमीटर हो गई है।
- इससे इस क्षेत्र में 4जी/5जी मोबाइल सेवाओं के रॉल-आउट को बढ़ावा मिला है।
- सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिनांक 31.12.2023 तक कुल 2,229 टावर चालू किए गए हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को उच्च गुणवत्ता और उच्च गति की इंटरनेट पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड (बीएससीसीएल), बांग्लादेश से होकर कॉक्स बाजार/कुआकाटा से अगरतला तक नवंबर 2021 और अप्रैल 2022 में 10 जीबीपीएस (गीगा बाइट्स प्रति सेकंड) के दो इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय लिंक किराए पर लिए गए हैं।

देश में दूरसंचार कनेक्टिविटी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सरकार विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।

- लगभग 55 हजार गांवों में 4जी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 41,331 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कुल 41,160 मोबाइल टावरों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
- सभी बसे हुए गांवों को कनेक्ट करने के लिए 1.88 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से भारतनेट कार्यक्रम के दायरे का विस्तार किया गया है।

*****